

राजस्थान सरकार साहिबजादों के नाम छात्रावास के लिए भूमि देगी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा कार्यालय में शबद कीर्तन कार्यक्रम में यह घोषणा की

जयपुर, 26 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर बाल दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में शबद कीर्तन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार साहिबजादों के नाम पर छात्रावास के लिए सिख समाज को जमीन का आवंटन करेगी। उन्होंने कहा कि सिख धर्म के दसवें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने मातृ भूमि के लिए,

■ मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा का संकल्प है कि सिख धर्म के साहिबजादों के बलिदान को देश की युवा पीढ़ी को बताया जाये और उनके आदर्शों पर चलने के लिये प्रेरित किया जाये।



वीर बाल दिवस पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित शबद कीर्तन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने साहिबजादों के नाम पर छात्रावास के लिए सिख समाज को जमीन का आवंटन करने की घोषणा की।

अपनी संस्कृति और विचारों के लिए दृढ़ता के साथ अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनको मेरा कोटि-कोटि नमन। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने धर्म की रक्षा और सत्य के लिए अल्प आयु में ही अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यह हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अत्याचारी मुगल शासकों ने उन्हें झुकाने और उनका काम परिवर्तन करवाने के लिए अनेक अत्याचार किए,

लेकिन राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादों ने हंसते हुए मृत्यु को गले लगा लिया। साहिबजादों की शहादत हमें बताती है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उम्र नहीं, दृढ़ संकल्प और साहस की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि ऐसी माता को भी नमन, जिसने अपने बच्चों में राष्ट्र और धर्म के लिए ऐसे संस्कार और शिक्षा दी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि सिख धर्म के इन साहिबजादों के बलिदान को देश

की युवा पीढ़ी को बताया जाए और देश के युवा वर्ग को इनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साहिबजादों के शहादत को राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित कर उनकी स्मृति को चिर स्थाई बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मुगलों ने इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए साहिबजादों को यातनाएं दीं, लेकिन उन्होंने सिर झुकाने की बजाय, अपने प्राण न्यौछावर करना

उचित समझा। राठौड़ ने कहा कि आज समय के अनुसार हमें जागृत रहने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम समिति के प्रदेश संयोजक प्रणवेन्द्र शर्मा ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय के साथ, प्रदेशभर में वीर बाल दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भाजपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सी आर चौधरी सहित, भाजपा के अनेक गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

नीट पीजी में सेवारत चिकित्सकों को बोनस अंक क्यों नहीं दिये?

जयपुर, 26 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट पीजी-2024 में सेवारत चिकित्सक को बोनस अंकों का लाभ नहीं देने पर स्वास्थ्य विभाग और नीट पीजी बोर्ड के चेयरमैन से जवाब तलब किया है।

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश डॉ. लोकेश कुमारी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि एएमएस मेडिकल कॉलेज ने नीट के जरिए मेडिकल पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए गत 23 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर काउंसिलिंग प्रक्रिया आरंभ की, जिसके अनुसार, अभ्यर्थियों को प्रथम राउंड की काउंसिलिंग के लिए 18 नवंबर तक पंजीकरण करना था। याचिकाकर्ता चिकित्सक प्रथम राउंड की काउंसिलिंग में अपना पंजीकरण नहीं करा सकी। वहीं दूसरी ओर, 16 नवंबर, 2024 को विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह शर्त लगा दी कि यदि कोई सेवारत चिकित्सक इन सर्विस कैटेगरी में बोनस अंक का लाभ लेना चाहे तो उसे प्रथम राउंड की काउंसिलिंग में पंजीकरण करना होगा। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वितीय

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और नीट पीजी बोर्ड चेयरमैन से जवाब मांगा।

और अन्य राउंड की काउंसिलिंग के लिए पात्र है, लेकिन इस शर्त से याचिकाकर्ता चिकित्सक को बोनस अंकों का लाभ नहीं मिल पाएगा और उसे मनचाहे विषय की सीट आवंटित नहीं हो पाएगी।

याचिका में कहा गया कि पूर्व के सालों में स्टेट काउंसिलिंग के दौरान सभी राउंड की काउंसिलिंग में सेवारत चिकित्सकों को उनकी ग्रामीण सेवा में की गई सेवा के अनुसार, इन सर्विस कैटेगरी के तहत, बोनस अंकों का लाभ दिया जाता रहा है। वहीं, नीट-2024 के प्रारंभिक नोटिफिकेशन में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था कि प्रथम चरण के बाद अन्य चरणों में सेवारत चिकित्सकों को बोनस अंकों से वंचित रखा जाएगा।

इसके अलावा, किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश या भर्ती प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में याचिकाकर्ता को बोनस अंकों का लाभ दिया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

प्र.मंत्री मोदी एक ही दिन में 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स का ई वितरण करेंगे

स्वामित्व योजना के तहत इस कार्य के लिए 46 लाख गांवों का चयन किया गया है

नयी दिल्ली, 26 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 200 जिलों के 46,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को यहां बताया कि सर्वेक्षण की नवीनतम डेटा तकनीक के माध्यम से गांवों में घरों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने स्वामित्व

■ ये 46,000 गांव दस राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इन राज्यों में राजस्थान भी शामिल है।

योजना शुरू की थी। यह योजना संपत्तियों के मुद्र्रीकरण और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण को सक्षम करने, संपत्ति से संबंधित विवादों का समापन करने, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों और संपत्ति कर के बेहतर मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करने और

व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना को सक्षम करने में भी मदद करती है। अभी तक 3 लाख दस हजार से अधिक गांवों में डेटा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें लक्षित गांवों का 92 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। अब तक लगभग डेढ़ लाख गांवों के लिए लगभग 2 करोड़ 20 लाख संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

यह योजना त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों तथा कई केंद्र शासित प्रदेशों में डेटा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

कांग्रेस माकन पर 24 घंटे में कार्यवाही करे- आतिशी

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानों को लेकर टकराव शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को कहा, कांग्रेस नेता अजय माकन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को एंटी-नेशनल कहते हैं। क्या उन्होंने भाजपा के किसी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया। आतिशी ने कहा, हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि वह माकन के खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करे। वरना हम इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी को अलग करने के लिए अन्य विपक्षी दलों से बात करेंगे।

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भाजपा के पक्ष में खड़ी हो गई है। कांग्रेस हर वो

■ मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा वे इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस को निकालने की मांग करेंगी।

■ अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग, यानी सबसे बड़ा धोखेबाज बताया।

काम कर रही है, जिससे भाजपा को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन। वे भाजपा की रिक्रूट पट्टे ते हैं। वे भाजपा के कहने पर

15 लाख रूपए सालाना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सात से दस लाख रूपए की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रूपए की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रूपए आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रूपए से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है।

वर्तमान में करदाता दोनों सिस्टम में मकान किराए, बीमा आदि खर्चों पर टैक्स राहत दी जाती है। इसमें रेट्स कम है, पर कटौती भी कम है। टैक्स में कटौती से ज्यादा लोग नई टैक्स प्रणाली की तरफ आकर्षित होंगे।

टैक्स कटौती कितनी होगी, यह अभी तय नहीं है। इस बारे में एक फरवरी तक निर्णय हो सकता है। दस लाख रूपए या उससे अधिक कमाने वाले लोग, जो बहुत ही कम, हमारी कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत मात्र है, आयकर से प्राप्त

■ इस प्रावधान से सरकार मध्यम वर्ग को ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, जो हाई टैक्स और बढ़ती महंगाई से त्रस्त है।

राजस्व में सर्वाधिक 70 प्रतिशत योगदान देते हैं। इस ग्रुप में प्रोफेशनल्स, व्यापारी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो 30 प्रतिशत की दर से टैक्स देते हैं।

भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने हाल ही में जुलाई-सितम्बर की तिमाही में गत सात तिमाही की सबसे कम ग्रोथ देखी थी, इससे उपभोक्ता मांग के बारे में चिंता बढ़ गई थी। खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों की

वजह से शहरी क्षेत्रों में लज़री आईटम्स पर खर्च कम हुआ है, जिनमें साबुन, शैम्पू और ऑटो मोबाइल प्रमुख हैं। मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने से आर्थिक सक्रियता बढ़ सकती है। सरकार पर इस वर्ग का दबाव है। वह हाई टैक्स और कम वेतन वृद्धि तथा बढ़ती महंगाई से त्रस्त है।

आर.एस.एस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सिविलिटाइज़ेशनल जस्टिस की इस तलाश को संबंधित करने का उचित समय आ गया है।' संपादकीय में आगे कहा गया है: "बाबासाहेब अंबेडकर ने जाति-आधारित भेदभाव की जड़ से निपटने के लिये संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराये थे, ताकि इसे उखाड़ फेंका जाए।

पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी का गुजारा भत्ता तय किया

जयपुर, 26 दिसंबर। पारिवारिक न्यायालय क्रम-1 महानगर प्रथम ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में कहा है कि पत्नी का भरण-पोषण करना पति का विधिक व नैतिक दायित्व है। न्यायालय ने अप्रार्थी पति को निर्देश दिया है कि वह प्रार्थिया पत्नी को हर महीने भरण-पोषण के लिये 15 हजार रूपए भुगतान करे। न्यायालय ने कहा कि अप्रार्थी पति की ओर से अपनी आय के संबंध में दिए जवाब व स्टेटमेंट में गंभीर विरोधाभास है। उसने आय के संबंध में तथ्यों को छिपाया है। अप्रार्थी का यह कहना, कि वह अपने पिता के साथ रंगाई काम से तीन से चार हजार रूपए कमाता है, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। मामले

■ पति ने आय के तथ्यों को छिपाया। न्यायालय ने 40 हजार आय मान कर 15 हजार रूपए गुजारा भत्ता तय किया।

के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अप्रार्थी की आय 40 हजार रूपए माना जाना सही है। पीठासीन अधिकारी विवेन्द्र कुमार जसूजा ने यह आदेश पत्नी के प्रार्थना पत्र पर दिए।

मामले के अनुसार, प्रार्थिया का निकाह 14 दिसंबर 2012 को अप्रार्थी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष का व्यवहार प्रार्थिया से अच्छा नहीं रहा और वे उसे देहेज के लिए शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगे। उन्होंने उससे तीन लाख रूपए नगद व एक कार की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। प्रार्थिया बेरोजगार है और पति विदेश में काम कर 80 हजार रूपए कमाता है। ऐसे में उसे भरण पोषण भत्ता दिलाया जाए।

भाजपा महिला मोर्चा का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन

नयी दिल्ली, 26 दिसम्बर। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महिला मोर्चा ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को छलने और महिला सम्मान के नाम पर झूठी तसल्ली देने का आरोप लगाया। मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा

■ उन्होंने केजरीवाल पर महिलाओं को छलने का आरोप लगाया।

पांडेय मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष योगिता सिंह, मोर्चा की प्रभारी श्याम बाला, प्रदेश प्रवक्ता एवं निगम पाषंद शिखा राय, मोर्चा महासूत्री प्रियल भाद्राज, प्रदेश उपाध्यक्ष शिखा माथुर, संगीता चौधरी, रेखा सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुईं।

'बेलगावी बैठक में कांग्रेस के भविष्य का एजेंडा तय होगा'

पायलट व शिवकुमार ने कार्यसमिति की बैठक का महत्व रेखांकित किया

महात्मा गांधी नगर, बेलगावी 26 दिसंबर। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और सचिन पायलट ने गुरुवार को यहां कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान पार्टी के भविष्य की रूपरेखा तय की।

यह बैठक महात्मा गांधी द्वारा 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित की गयी है।

इस मौके पर शिवकुमार ने अपने संबोधन में देश को एकजुट करने और राजनीतिक सत्ता की परवाह किए बिना समाज के सभी वर्गों की सेवा करने में कांग्रेस पार्टी की दीर्घकालिक भूमिका पर जोर दिया।

सहित कि पार्टी को विरासत राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में गहराई से, यहां तक कि प्रतिकूल समय में भी निहित है।

इस अवसर पर राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बैठक को संबोधित करते हुए शताब्दी के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया

■ महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन की शताब्दी के उपलक्ष्य में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक यहां आयोजित की गई है।

और इसे कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा, यह बैठक हमारी पार्टी के भविष्य के एजेंडे के लिए आधार तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि वह राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। उन्होंने आने वाले वर्षों में पार्टी के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करने में बैठक के महत्व को भी रेखांकित किया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज दोपहर 15 बजे शुरू हुई, जो 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। ऐतिहासिक महत्व रखने

वाले इस स्थल का नाम बदलकर इस अवसर के सम्मान में महात्मा गांधी नवगनर रखा गया है।

बैठक में इंडिया समूह को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कांग्रेस नेतृत्व ने आने वाले महीनों में गठबंधन को मजबूत करने और राजनीतिक विरोधियों का मुकाबला करने की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की।

कांग्रेस ने कार्यसमिति की बैठक के अलावा 27 दिसंबर को बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम 'जय बापू-जय भीम-जय संविधान' की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है।

राजस्थान भीषण ठंड की चपेट में

■ दिल्ली-एन.सी.आर. में 3 दिन तेज बारिश का चलो अलर्ट।

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर। दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में तीन दिनों तक बारिश का चलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, एनसीआर के लोगों को 27 और 28 दिसंबर को तेज बारिश और तेज हवा का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। बारिश के बाद, लोगों को घने कोहरे और तापमान में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक, 27 और 28 दिसंबर को तुफान के साथ तेज बारिश हो सकती है।

राजस्थान के अधिकतर इलाके भीषण ठंड की चपेट में हैं और मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार से राज्य में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। मौसम केंद्र, जयपुर के अनुसार, बीते 24 घंटे में राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। इस दौरान कहीं-कहीं घने से अति घना कोहरा छाया रहा और पश्चिमी राजस्थान में 'शीत दिवस' दर्ज किया गया। 27 दिसंबर को कुछ जगहों पर बारिश और

ओलावृष्टि का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 दिसंबर को कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने और शेष अधिकांश भाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि 29 दिसंबर से मौसम शुष्क रहेगा तथा कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहेगा व तापमान में गिरावट हो सकती है।

कश्मीर भयंकर शीतलहर की चपेट में है और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। शुक्रवार और शनिवार को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है, क्योंकि क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होने की संभावना है। कश्मीर घाटी में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे घाटी में ठंड का प्रकोप जारी रहा। पारे में गिरावट के कारण, विभिन्न क्षेत्रों में कई जलाशयों और जलाशयों लिट्टान में पानी जम गया है। मौसम विभाग के अनुसार, 29, 30 और 31 दिसंबर को मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा।

डॉ. मनमोहन सिंह का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गए हैं। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे देर रात दिल्ली पहुंचे। प्रियंका गांधी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एम्स पहुंचे।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। वह संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह ने 21 मार्च, 1998 से 21 मई 2004 तक सदन में नेतृत्व प्रोत्साहित किया।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एएनपी मनी अवार्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम मिथ पुरस्कार, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार शामिल हैं।

डॉ. सिंह को जापानी निहोने किजई शिम्बुन एवं अन्य संघों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। डॉ. सिंह को कैब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियां प्रदान की गईं।

स्वीकृत संख्या है। इस समय हाई कोर्ट में 32 न्यायाधीश नियुक्त हैं। इन तीन नए जजों के मिलने के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी स्वीकृत संख्या से 15 न्यायाधीश कम रहेंगे। इसके अलावा, साल 2025 में पांच न्यायाधीश रिटायर भी हो जाएंगे। जनवरी माह में जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस मदन गोपाल व्यास, मई में जस्टिस वीरेंद्र कुमार, सितंबर में जस्टिस नरेन्द्र बड्डा और नवम्बर में जस्टिस मनोज कुमार गंग रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में, हाई कोर्ट में जजों की संख्या घटकर 30 हो रहने वाली है। हालांकि संभावना है कि नए साल में अधिवक्ता कौन से राजस्थान हाईकोर्ट को कुछ नए जज और मिल सकते हैं।

■ सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर व चंद्र प्रकाश श्रीमाल के नाम की सिफारिश की।

स्वीकृत संख्या है। इस समय हाई कोर्ट में 32 न्यायाधीश नियुक्त हैं। इन तीन नए जजों के मिलने के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 35 हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी स्वीकृत संख्या से 15 न्यायाधीश कम रहेंगे। इसके अलावा, साल 2025 में पांच न्यायाधीश रिटायर भी हो जाएंगे। जनवरी माह में जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस मदन गोपाल व्यास, मई में जस्टिस वीरेंद्र कुमार, सितंबर में जस्टिस नरेन्द्र बड्डा और नवम्बर में जस्टिस मनोज कुमार गंग रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में, हाई कोर्ट में जजों की संख्या घटकर 30 हो रहने वाली है। हालांकि संभावना है कि नए साल में अधिवक्ता कौन से राजस्थान हाईकोर्ट को कुछ नए जज और मिल सकते हैं।

सी.डब्ल्यू.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) महाराष्ट्र चुनावों को लेकर अपनी चिन्ताएं सामने रखीं तथा कहा कि मतदान बढ़ कैसे गया था। इस बिन्दु का समापन करते हुये, उन्होंने कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन नेतृत्व, चुनाव प्रक्रिया पर तथा मतदान ई वी चयन के जरिये हो या मतपत्र के जरिये हो- पर पूरी तरह स्पष्ट विचार देने में असमर्थ रहा।

गत वर्ष में तीन सर्वोच्च स्तर के सेना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के वफादार सदस्य थे। तथापि, शीर्ष सैन्य अधिकारियों के चयन में केवल शी जिनपिंग के प्रति वफादारी ही महत्वपूर्ण है।

उच्च सैन्य अधिकारियों की इस तरह से बर्खास्तगी से शी के काम करने के तरीके तथा शीर्ष अधिकारियों के उनके चयन की ही धक्का लगा है। आखिरकार, किसी और ने नहीं, बल्कि शी जिनपिंग ने स्वयं ही इन अधिकारियों का चयन किया था। इनको बर्खास्त करके, सुप्रीम लीडर अपने ही चयन के विरुद्ध एकात्मत रहे थे।

कुल संख्या की दृष्टि से, चीन का मिलिटरी सिस्टम विश्व में सबसे बड़ा है। चीन की मिलिटरी में करीब दो करोड़ डायरेक्ट सदस्य हैं। मिलिटरी हाईवेयर में भी चीन की सैन्य प्रणाली सबसे बड़ी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी

के पास युद्धपोतों और नेवल वैसलस पर बहुत बड़ा बेड़ा है। इसके पास दुनिया में सबसे अधिक सैनिक हैं।

लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि यह सबसे मजबूत है। चीन की सेना ने जब विधानमंच पर हमला किया था तो उस छोटे से देश ने चीन की सेना को एक तरह से हरा ही दिया था। भ्रष्टाचार के अभाव पर बर्खास्तगी का लगातार बना हुआ खतरा तथा अनिश्चितताएं चीन की सेना को कुछ हद तक कमजोर बनाते हैं।

साथ ही, चीन की सेना में भ्रष्टाचार का अवसर बना रहता है, क्योंकि सेना पर बहुत बड़ी रकम खर्च होती है, खासतौर पर सेना के उपकरणों और सुविधाओं पर। अधिकारियों और अक्सर मिलिटरी रीफिटिंग में पैसा निकालने का आरोप लगाया जाता है।